प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांकः 16 मार्च, 2018**

विषयः- **मै0 मिडएप्पल फूड प्रोडेक्टस, ई-10, रोड नं0-3 परसाखेड़ा, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बरेली को उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के योजनान्तर्गत ब्याज उपादान हेतु स्वीकृत अनुदान की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त हेतु कुल धनराशि रू0-8.58 लाख (रूपया आठ लाख अट्ठावन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0उ0नि0-2656/48/ब्याज उपादान/2017-18, दिनांक-06.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1/997/58-2-2013-10/12टी0सी0-1, दिनांक- 06.12.2013 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांकः 09.01.2018 एवं 15.02.2018 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर **मै0 मिडएप्पल फूड प्रोडेक्टस, ई-10, रोड नं0-3 परसाखेड़ा, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बरेली** को उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 योजनान्तर्गत ब्याज उपादान हेतु बैंक् द्वारा प्राप्त किये गये वास्तविक ब्याज के सापेक्ष नीति में प्राविधानित 07 प्रतिशत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-21/2017/289/58-2-2017-300(14)/2016, दिनांक-15/05/2017 द्वारा रू0-84.60 लाख, शासनादेश संख्या-27/2017/776/58-2-2017-300(7)/2017, दिनांक-28/08/2017 द्वारा रू0-118.45 लाख तथा पुनर्विनियोग के माध्यम से शासनादेश संख्या-34/2017/1198/58-2-2017-300(15)/2017, दिनांक-16.11.2017 द्वारा रू0-224.07 लाख एवं संख्या-03/2018/228/58-2-2018-10/2012, दिनांक-06.02.2018 द्वारा रू0-1500.00 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में ब्याज के रूप में भुगतान की गयी वास्तविक धनराशि के सापेक्ष उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के तहत अनुमन्य 07 प्रतिशत की दर से अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आकलित अनुमन्य ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति धनराशि **रू0-8.58 लाख (रूपया आठ लाख अट्ठावन हजार मात्र)** को **प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त** के रूप में प्रतिपूर्ति हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012-में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं अनुबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-65/58-2-2013-10/2012, दिनांक-21.01.2013 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाया।

(3) अनुदान हेतु स्वीकृत प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए निदेशक, उद्रयान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन उत्तरदायी होंगे।

(4) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2018 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(8) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्रयान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ निदेशक, मिशन तथा वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(9) राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(10) योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को भुगतान किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0,ए, दिनांक: 29.05.2012 का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(11) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2017/बी-1-02/दस-2017-201/2017, दिनांक-02.02.2017 ,संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 एवं संख्या-12/2017/बी-1-1455/ दस- 2017-231/2017, दिनांक- 20.11.2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जारहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-08/2018/376(1)/58-2-2018, तद्दिनांक:

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) आयुक्त/जिलाधिकारी, बरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in